to $ 100 million in India for any product in telecom sector;

(b) whether it is also a fact that Motorola has withdrawn this offer as no decision was taken for a considerable period;

(c) if so, when the offer was made and when it was withdrawn;

(d) whether it is also a fact that the Chairman of Motorola wrote to the Government of India indicating the withdrawal of their offer and stating that they are investing this amount in China; and

(e) if so, what are the details in this regard ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI P. V. RANGAYYA NAIDU) : The question has already been answered by Ministry of Industry on 26-11-92 vide Q. No. 638. Reply is reproduced below :

(a) Motorola Inc. USA had represented a perspective plan for an investment of over 100 million dollars in diverse sectors over a period of time. More specifically they have made 2 proposals with foreign equity amounting to US $ 4.8 million which has since been approved.

(b) to (d) There is no reference in the letter from Chairman, Motorola to Prime Minister regarding the withdrawal of this offer in favour of China.

(e) Does not arise.

संचार मंत्रालय के खर्च में कमी करने के लिए उपाय

1201. श्री ईश दत्त यादव : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खर्च में कमी करने के लिए उनके मंत्रालय द्वारा किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है, और

(ख) इन उपायों के कार्यान्वयन से कितनी धनराशि की बचत हुई है ?

संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी० वी० रंगैया नायडू) : (क) खर्च में कमी करने के लिए किए गए उपाय निम्नलिखित हैं :

(i) पद्धतियों का सरलीकरण करके प्रचालन लागतों में कटौती करना,

(ii) नई प्रौद्योगिकी लागू करना,

(iii) समयोपरि भत्ते, यात्रा व्यय और पैट्रोल के उपभोग जैसे मामलों में सरकार द्वारा जारी किए गए वित्तीय अनुदेशों को सख्ती से लागू करना।

दूरसंचार विभाग में, जहां सेवाओं में तेजी के साथ वृद्धि हो रही है, बढ़े हुए कार्य-भार का संचालन, कर्मचारियों की संख्या में न्यूनतम वृद्धि करके किया जाता है।

(ख) बचत की सही राशि बता पाना कठिन है। लेकिन डाक विभाग में 1991-92 के दौरान 1525.10 करोड़ रु० के बजट अनुमान की तुलना में 1506.75 करोड़ रु० का राजस्व व्यय हुआ। इसी प्रकार, दूरसंचार विभाग में 2490.00 करोड़ रु० के बजट अनुमान की तुलना में 2424.38 करोड़ रु० का राजस्व व्यय हुआ।

महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड में अधिकारियों की संख्या में वृद्धि

1202. चौधरी हरमोहन सिंह : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड में प्रथम श्रेणी के अधिकारियों की संख्या में गत छः वर्ष की तुलना में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो 1 अप्रैल, 1986 की स्थिति के अनुसार विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी थी;

(ग) सितम्बर, 1992 में श्रेणीवार कर्मचारियों की संख्या कितनी थी और इन छः वर्षों के दौरान कितने पदों का सृजन किया गया है; और

7—407 RSS/93

(घ) क्या सरकार प्रथम श्रेणी के अधिकारियों की संख्या में कमी करने पर विचार करेगी ताकि प्रशासनिक व्यय में कमी की जा सके।

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगैया नायडू) : (क) जी हां, इस अवधि के दौरान टेलीफोनों की संख्या 7,46,000 से बढ़कर 14,35,000 अर्थात दुगुनी हो गई है। सभी समूहों के कर्मचारियों में वृद्धि हुई है। तथापि, श्रेणी I के अधिकारियों का प्रतिशत कुल अधिकारियों की तुलना में कुछ हद तक कम हुआ है :

(ख) 1 अप्रैल, 1986 की स्थिति के अनुसार कर्मचारियों की संख्या श्रेणीवार इस प्रकार है :

समूह क	361	कुल अधिकारियों का 26.6 प्रतिशत
समूह ख	995	कुल अधिकारियों का 73.4 प्रतिशत
समूह ग	34946	
समूह घ	8104	

(ग) 30 सितम्बर, 92 की स्थिति के अनुसार कर्मचारियों की संख्या इस प्रकार है :—

समूह क	677	कुल अधिकारियों का 25.5 प्रतिशत
समूह ख	1976	कुल अधिकारियों का 74.5 प्रतिशत
समूह ग	35190	
समूह घ	16999	

गत छह वर्षों के दौरान सृजित पदों की संख्या इस प्रकार है :—

समूह क	338
समूह ख	1173
समूह ग	4538
समूह घ	10733

(घ) टेलीफोनों के बड़े पैमाने पर वृद्धि के परिणामस्वरूप बढ़े हुए कार्य को संभालने के लिए अधिकारियों के सभी संवर्गों में वृद्धि की जानी है।

Waiting list of Telephone Connections in the Country

1203. SHRI S. K. T. RAMACHANDRAN: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state :

(a) what is the number of persons waiting for telephone connection as at the end of 1991-92 and so far upto September, 1992 in the whole country, State-wise; and

(b) what steps are being taken to clear the mounting backlog in the waiting list ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI P. V. RANGAYYA NAIDU) : (a) State-wise detail of waiting list is placed at statement (*see* below).

(b) A target of provision of 8.5 lakh new telephone connections has ben fixed for the year 1992-93 subject to the availability of equipment and resources. The remaining applicants are proposed to be provided with telephone connections during the 8th Five Year Plan period which envisage to provide telephone connections practically on demand in rural and tribal areas.

Waiting period for telephone connections not to exceed two years for large telephone systems.

The expansion plans are being drawn accordingly.